भारत सरकार
पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय

लोक सभा
तारांकित प्रश्न संख्या : 274
दिनांक 06 अगस्त, 2026

कच्चे तेल का उत्पादन

†*274. **श्रीमती महुआ मोइत्राः**

क्या ***पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस*** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) विगत तीन वर्षों के दौरान अपतटीय और तटवर्ती दोनों क्षेत्रों से कच्चे तेल के घरेलू उत्पादन का वर्ष-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या उक्त अवधि के दौरान तेल और प्राकृतिक गैस निगम (ओएनजीसी) और ऑयल इंडिया लिमिटेड (ओआईएल) के प्रमुख पुराने क्षेत्रों से उत्पादन में गिरावट आई है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने पॉलीमर फ्लडिंग और माइक्रोबियल ईओआर सहित संवर्धित तेल निकासी (ईओआर) और उन्नत तेल निकासी (आईओआर) संबंधी परियोजनाओं का प्रस्ताव किया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(घ) क्या सरकार ने उन्नत भूकंपीय इमेजिंग और डिजिटल तेल क्षेत्र प्रौद्योगिकियों का उपयोग करते हुए जलाशयों का पुनर्मूल्यांकन किया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) वर्ष 2030 तक घरेलू कच्चे तेल के उत्पादन में ईओआर के अनुमानित योगदान का ब्यौरा क्या है?

उत्तर
पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री
(श्री हरदीप सिंह पुरी)

(क) से (ङ): एक विवरण सदन के पटल पर रख दिया गया है।

'कच्चे तेल का उत्पादन' के बारे में संसद सदस्य श्रीमती महुआ मोइत्रा द्वारा दिनांक 06.08.2026 को पूछे गए लोक सभा तारांकित प्रश्न सं. 274 के भाग (क) से (ङ) के उत्तर में उल्लिखित विवरण।

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान ऑफशोर और ऑनशोर क्षेत्रों से कच्चे तेल का घरेलू उत्पादन नीचे तालिका में दिया गया है:

तेल (मिलियन मीट्रिक टन, एमएमटी)	2023-24	2024-25	2025-26
ऑफशोर	15.03	15.09	14.83
ऑनशोर	14.33	13.61	13.13
कुल योग	29.36	28.70	27.96

(ख) पिछले तीन वर्षों में घरेलू तेल उत्पादन में थोड़ी गिरावट आई है, जिसका मुख्य कारण पुराने हो रहे तेल और गैस क्षेत्रों में प्राकृतिक रूप से उत्पादन का कम होना है। विवरण इस प्रकार हैं:-

तेल (एमएमटी)	2023-24	2024-25	2025-26
ओएनजीसी (नामांकन)	19.21	18.47	17.80
ओआईएल (नामांकन)	3.34	3.44	3.43
योग	22.56	21.91	21.23

हालाँकि, इस अवधि के दौरान, राष्ट्रीय तेल कंपनियों (एनओसी) अर्थात् ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन (ओएनजीसी) लिमिटेड और ऑयल इंडिया लिमिटेड (ओआईएल) ने लगातार अपने उत्पादन स्तर को बनाए रखा है। यह ध्यान दिया जा सकता है कि एनओसी 2014-15 से वार्षिक गिरावट दर को लगभग 2% तक सीमित रखने में सक्षम रहे हैं, जो परिपक्व क्षेत्रों के लिए 6% की वैश्विक औसत गिरावट दर (अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी के अनुसार) से 3 गुना बेहतर है।

(ग) और (घ) सरकार संवर्धित तेल पुनः प्राप्ति (ईओआर), बेहतर तेल पुनः प्राप्ति (आईओआर), या रिजर्वायर पुनर्मूल्यांकन के लिए प्रत्यक्ष रूप से क्षेत्र-स्तरीय परियोजनाओं को लागू नहीं करती है। रिजर्वायर प्रबंधन और उपयुक्त निकासी तकनीकों के चयन की जिम्मेदारी अन्वेषण और उत्पादन (ई एंड पी) ऑपरेटरों के पास है। इस तरह की परियोजनाएं तेलक्षेत्र (विनियमन और विकास) अधिनियम, 1948 और पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस नियम, 2025 के तहत स्थापित वैधानिक और विनियामक ढांचे के भीतर कार्य करती हैं, जो पेट्रोलियम संसाधनों के व्यवस्थित और कुशल विकास के लिए प्रावधान करती हैं।

सरकार नीतिगत प्रोत्साहन, बेसिन-स्तरीय अध्ययन और तकनीकी निरीक्षण के माध्यम से इन प्रयासों का समर्थन करती है। बेसिन स्तर पर हाइड्रोकार्बन संसाधन क्षमता को बेहतर ढंग से समझने के लिए, सरकार ने हाइड्रोकार्बन संसाधन मूल्यांकन अध्ययन (एचआरएएस) को वित्त पोषित किया है, जिसके माध्यम से वर्ष 2017 में भारत के तलछटी बेसिनों का व्यापक पुनर्मूल्यांकन किया गया था।

ई एंड पी ऑपरेटरों द्वारा शुरू की गई ईओआर/आईओआर और रिजर्वायर पुनर्मूल्यांकन पहलों का विवरण अनुलग्नक-I है।

इसके अलावा, कैबिनेट ने बड़े पैमाने पर अधिग्रहण, प्रसंस्करण और उच्च गुणवत्ता वाले भूकंपीय डेटा की व्याख्या, गहरे क्षेत्र और अति-गहरे क्षेत्रों में त्वरित खोजपूर्ण ड्रिलिंग, सामान्य बुनियादी ढांचे और तेल और गैस विनिर्माण क्षेत्र के विकास के साथ-साथ 'समुद्र मंथन' - राष्ट्रीय ऑफशोर अन्वेषण योजना को 31.07.2026 को मंजूरी दी है। योजना का विवरण अनुलग्नक-II में है।

(ङ) ईओआर एक केंद्रीय रूप से निष्पादित उत्पादन कार्यक्रम नहीं है और इसलिए 2030 के लिए इसके योगदान को एक अलग राष्ट्रीय लक्ष्य के रूप में नहीं दर्शाया गया है। ईओआर परियोजनाओं की योजना बनाई जाती है और रिजर्वायर की विशेषताओं, तकनीकी व्यवहार्यता और आर्थिक व्यवहार्यता के आधार पर व्यक्तिगत ई एंड पी ऑपरेटर द्वारा क्षेत्रवार कार्यान्वित की जाती है। ऐसी परियोजनाओं से अपेक्षित वृद्धिशील उत्पादन संबंधित क्षेत्र विकास और उत्पादन योजनाओं का हिस्सा है और इसे समय-समय पर पायलट परिणामों, वास्तविक रिजर्वायर प्रतिक्रिया, परियोजना कार्यान्वयन कार्यक्रम और प्रचलित तकनीकी-आर्थिक स्थितियों के प्रकाश में संशोधित किया जाता है। तदनुसार, 2030 तक घरेलू कच्चे तेल के उत्पादन में ईओआर का योगदान पट्टेदारों द्वारा कार्यान्वित विभिन्न परियोजनाओं से प्राप्त वृद्धिशील उत्पादन का कुल योग होगा।

*****

अनुलग्नक-I

'कच्चे तेल का उत्पादन' के बारे में संसद सदस्य श्रीमती महुआ मोइत्रा द्वारा दिनांक 06.08.2026 को पूछे गए लोक सभा तारांकित प्रश्न सं.274 के भाग (ग) से (घ) के उत्तर में उल्लिखित अनुलग्नक।

क. प्रमुख ईओआर/आईओआर पहलों का विवरण

1. तेल और प्राकृतिक गैस निगम (ओएनजीसी) लिमिटेड

i. ओएनजीसी 1987 से संवर्धित तेल पुनः प्राप्ति (ईओआर) विधियों के कार्यान्वयन में अग्रणी रही है, जिसने आज तक 22 से अधिक पायलट और वाणिज्यिक परियोजनाओं को सफलतापूर्वक निष्पादित किया है।

ii. वर्तमान में, गुजरात, असम और मुंबई हाई में क्षेत्रों में ईओआर प्रौद्योगिकियों के एक व्यापक पोर्टफोलियो का कार्यान्वयन किया गया है।

iii. इनमें यथास्थान दहन, पॉलिमर बाढ़, क्षारीय-पृष्ठीय-पॉलिमर (एएसपी) बाढ़, कम लवणता जल बाढ़, सूक्ष्मजीवी ईओआर, मिश्रित गैस इंजेक्शन और अमिश्रणीय गैस इंजेक्शन शामिल हैं।

iv. ये उपाय परिपक्व जलाशयों में प्राकृतिक गिरावट को कम करने और मौजूदा क्षेत्रों से वसूली बढ़ाने के लिए ओएनजीसी के निरंतर कार्यक्रम का हिस्सा हैं।

v. ओएनजीसी कार्य-ओवर, कूप सिम्युलेशन, विकास ड्रिलिंग, कृत्रिम लिफ्ट की स्थापना और रिजर्वायर के दबाव रखरखाव के माध्यम से आईओआर भी करता है।

2. ऑयल इंडिया लिमिटेड (ओआईएल)

i. ऊपरी असम बेसिन के 17 जलाशयों में कम लवणता वाले पानी के इंजेक्शन का कार्यान्वयन किया गया है

ii. भारी तेल की पुनर्प्राप्ति के लिए, साइक्लिक स्टीम स्टिमुलेशन को 2018 से राजस्थान के बाघेवाला क्षेत्र में सफलतापूर्वक लागू किया गया है

iii. इसके अलावा, ओआईएल नियमित रूप से क्षेत्र-विशिष्ट आईओआर उपाय करता है जैसे कि कार्य-ओवर, कूप सिम्युलेशन, विकास ड्रिलिंग, कृत्रिम लिफ्ट की स्थापना और रिजर्वायर दबाव रखरखाव।

3. वेदांत लिमिटेड

i. वेदांत ने राजस्थान राज्य में ब्लॉक आरजे-ओएन-90/1 के भीतर अपने क्षेत्रों में रासायनिक संवर्धित तेल पुनः प्राप्ति (ईओआर) तकनीकों को सफलतापूर्वक लागू किया है।

ii. सभी प्रमुख उत्पादक क्षेत्रों, अर्थात् मंगला, भाग्यम, ऐश्वर्या और एनई में पूर्ण-क्षेत्र पॉलीमर बाढ़ को लागू किया गया है।

iii. मंगला क्षेत्र में एल्कली-सर्फेक्टेंट-पॉलीमर (एएसपी) बाढ़ कार्यान्वयन के साथ इस पहल का एक महत्वपूर्ण विस्तार किया गया है।

iv. ये उपाय वेदांता के अपने उत्पादन परिसंपत्तियों से वसूली बढ़ाने और मौजूदा क्षेत्रों से हाइड्रोकार्बन उत्पादन को अधिकतम करने के लिए चल रहे कार्यक्रम का हिस्सा हैं।

ख. रिजर्वायर पुनर्मूल्यांकन और डिजिटल तेल क्षेत्र की पहलों का विवरण

i. हाइड्रोकार्बन संसाधनों की पूरी क्षमता को अनलॉक करने और रिजर्वायर की विशेषता को बढ़ाने के लिए ऑपरेटरों द्वारा उन्नत भूवैज्ञानिक और डिजिटल प्रौद्योगिकियों की एक श्रृंखला तैनात की जा रही है। इनमें उन्नत भूकंपीय इमेजिंग, एआई/एमएल-संचालित व्याख्या वर्कफ़्लो, 3डी भूकंपीय डेटा पुनर्संसाधन, डिजिटल रिजर्वायर मॉडलिंग और सिमुलेशन और उन्नत कुआँ लॉगिंग शामिल हैं।

ii. ऑपरेटर डेटा-संचालित निर्णय लेने में सक्षम बनाने के लिए अपने ईएंडपी संचालन में सेंसर, एससीएडीए सिस्टम, आईओटी, एआई और उन्नत विश्लेषण सहित डिजिटल तेल क्षेत्र प्रौद्योगिकियों का भी लाभ उठा रहे हैं।

iii. रिजर्वायर मूल्यांकन नियमित क्षेत्र-स्तरीय भंडार मूल्यांकन और प्रबंधन गतिविधियों का एक अभिन्न अंग है। ऑपरेटर समय-समय पर अद्यतन भूवैज्ञानिक व्याख्या, कूपों के परिणाम, उत्पादन प्रदर्शन, दबाव डेटा और रिजर्वायर मॉडलिंग का उपयोग करके जलाशयों का पुनर्मूल्यांकन करते हैं।

*****

अनुलग्नक-II

'कच्चे तेल का उत्पादन' के बारे में संसद सदस्य श्रीमती महुआ मोइत्रा द्वारा दिनांक 06.08.2026 को पूछे गए लोक सभा तारांकित प्रश्न सं.274 के भाग (ग) से (घ) के उत्तर में उल्लिखित अनुलग्नक।

"समुद्र मंथन" का संक्षिप्त विवरण - राष्ट्रीय ऑफशोर अन्वेषण योजना

1. केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 2030-31 तक कार्यान्वयन के लिए 84,084 करोड़ रुपये के परिव्यय के साथ 'समुद्र मंथन' - राष्ट्रीय ऑफशोर अन्वेषण योजना को मंजूरी दी।

2. इस योजना में ऑफशोर तेल और गैस अन्वेषण और उत्पादन में तेजी लाने, तकनीकी क्षमता वृद्धि और विकसित भारत के दृष्टिकोण के साथ संरेखण के माध्यम से भारत की ऊर्जा सुरक्षा को मजबूत करने की परिकल्पना की गई है।

3. इस योजना में ऑफशोर हाइड्रोकार्बन क्षमता की समझ में सुधार के लिए बड़े पैमाने पर अधिग्रहण, प्रसंस्करण और उच्च गुणवत्ता वाले भूकंपीय डेटा की व्याख्या के लिए एक घटक शामिल है।

4. इस योजना में गहरे क्षेत्र और अति-गहरे क्षेत्रों में त्वरित खोजपूर्ण ड्रिलिंग की परिकल्पना की गई है।

5. इस योजना में निम्नलिखित घटक शामिल हैं:

क. सामान्य ऑफशोर उत्पादन और निकासी बुनियादी ढांचे का विकास।

ख. मेक इन इंडिया पहल के अनुरूप एक तेल और गैस विनिर्माण और सेवा क्षेत्र की स्थापना।

6. योजना दस्तावेज में डिजिटल कार्यक्रम प्रबंधन, क्षमता निर्माण, प्रौद्योगिकी अपनाने, हितधारक सहभागिता और अंतर्राष्ट्रीय पहुंच से संबंधित प्रावधान शामिल हैं।

7. इस योजना का उद्देश्य ऑफशोर संसाधन आकलन में सुधार, अन्वेषण गतिविधियों में वृद्धि, रोजगार सृजन, निवेश और ऑफशोर अन्वेषण पारिस्थितिकी तंत्र को मजबूत करने की परिकल्पना की गई है।